



पदोन्नति में आरक्षण हेतु मापदंड निर्धारण से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार

प्रलिस के लिये:

आरक्षण, पदोन्नति, सर्वोच्च न्यायालय, अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति, इंदरि साहनी केस, एम नागराज केस

मेन्स के लिये:

नरिणय और मामले, अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति से संबंघति मुद्दे, पदोन्नति में आरक्षण और इससे संबंघति वभिनिन मामले ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति के उम्मीदवारों के लिये पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु प्रतनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिये मापदंड तय करने से इनकार कर दिया ।

न्यायालय का यह फैसला देश भर में दाखलि उन याचिकाओं पर दिया गया है, जनिमें पदोन्नति में आरक्षण देने के तौर-तरीकों पर और स्पष्टता की मांग की गई थी ।

प्रमुख बदि

■ सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

○ डेटा एकत्र करने हेतु 'कैडर':

- न्यायालय ने पदोन्नति कोटा देने हेतु मात्रात्मक डेटा के संग्रह के उद्देश्य से इकाई के रूप में 'कैडर' का निर्धारण किया है, न कि वर्ग, समूह या संपूर्ण सेवा ।
- न्यायालय ने कहा कि यदि अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति के प्रतनिधित्व से संबंघति डेटा संग्रह पूरी 'सेवा' के संदर्भ में किया जाता है, तो पदोन्नति में आरक्षण की पूरी कवायद नरिर्त्थक हो जाएगी ।

○ कोई मापदंड नहीं:

- अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति समुदाय के पर्याप्त प्रतनिधित्व का प्रश्न निर्धारति करने के लिये संबंघति राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिये और न्यायालय प्रतनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिये कोई मानदंड निर्धारति नहीं कर सकता है ।

○ 'बी.के. पवतिरा' वाद (2019) के नरिणय को रद्द करना:

- मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिये इकाई के रूप में 'कैडर' की मान्यता के साथ न्यायालय ने 'बी.के. पवतिरा' वाद (2019) के नरिणय को रद्द कर दिया था ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि समूहों के आधार पर डेटा के संग्रह को मंजूरी देने वाला नषिकर्ष 'नागराज और जरनैल सहि' वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारति नयिमां के वपिरीत है ।
- न्यायालय ने माना कि 'नागराज और जरनैल सहि' वाद के फैसले का 'प्रत्याशति प्रभाव' होगा ।

○ समीक्षा का आदेश:

- सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पदोन्नति में प्रतनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के उद्देश्य से डेटा के संबंघ में समीक्षा की जानी चाहिये ।
- हालाँकि न्यायालय ने राज्यों के लिये समीक्षा करने हेतु "उचित" समय तय करने का नरिणय केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है ।

■ पृष्ठभूमि:

◦ पदोन्नति में आरक्षण:

- 1950 के दशक से केंद्र और राज्य सरकारें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के पक्ष में पदोन्नति में सीटें आरक्षण करने की नीति का पालन कर रही हैं क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं में नरिणय नरिमाण प्रक्रिया के स्तर पर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

◦ इंदिरा साहनी वाद 1992:

- पदोन्नति में आरक्षण की इस नीति को **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और शून्य माना गया क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के समय केवल प्रवेश के स्तर पर अनुच्छेद 16 (4) के तहत राज्य को पछिड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है।

- **77वें संवैधान संशोधन अधिनियम** द्वारा अनुच्छेद 16(4A) को शामिल किया गया।

◦ एम नागराज वाद 2006:

- इस मामले में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले (1992) में अपने पूर्व नरिणय को पलट दिया, जिसमें उसने एससी/एसटी (जो ओबीसी पर लागू था) को क्रीमी लेयर की अवधारणा में बाहर कर दिया था।
- SC ने संवैधानिक संशोधनों जसिके द्वारा अनुच्छेद 16 (4A) और 16 (4B) को जोड़ा गया था यह कहते हुए बरकरार रखा कि अनुच्छेद 16 (4) से संबंधित हैं तथा ये अनुच्छेद की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं करते हैं।
- इसने सार्वजनिक रोजगार में एससी और एसटी समुदायों के लोगों की संख्या को बढ़ाने हेतु तीन शर्तें भी रखीं:

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पछिड़ा होना चाहिये।
- सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव हो।
- आरक्षण नीति प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करेगी।

- न्यायालय ने कहा कि सरकार अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों हेतु पदोन्नति में कोटा तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि विशेष समुदाय पछिड़ा हुआ, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से लोक प्रशासन की समग्र दक्षता प्रभावित नहीं होगी।

- सरकार की राय मात्रात्मक आँकड़ों पर आधारित होनी चाहिये।

◦ जरनैल सहि वाद 2018:

- जरनैल सहि मामले (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने नागराज फ़ैसले को एक उच्च पीठ को संदर्भित करने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में यह कहकर अपने नरिणय को बदल दिया कि राज्यों को SC/ST समुदायों के पछिड़ेपन के मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- न्यायालय ने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के सदस्यों के लिये 'परिणामी वरिष्ठता के साथ त्वरित पदोन्नति' प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया था।

आरक्षण में पदोन्नति हेतु संवैधानिक प्रावधान:

- संवैधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पछिड़े वर्गों के पक्ष में नयिकृतियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 16(4A) के अनुसार, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकती हैं यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 16 (4B):** इसे 81वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें एक विशेष वर्ष के रिकित SC/ST कोटे को अगले वर्ष के लिये स्थानांतरित कर दिया गया।
- **अनुच्छेद 335:** के अनुसार, सेवाओं और पदों को लेकर SC और ST के दावों पर विचार करने हेतु विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें बराबरी के स्तर पर लाया जा सके।
- 82वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 ने अनुच्छेद 335 में एक शर्त सम्मिलित की जो कि राज्य को किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

